मार्च, 2024, वर्ष : 45 अंक : 03 www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश

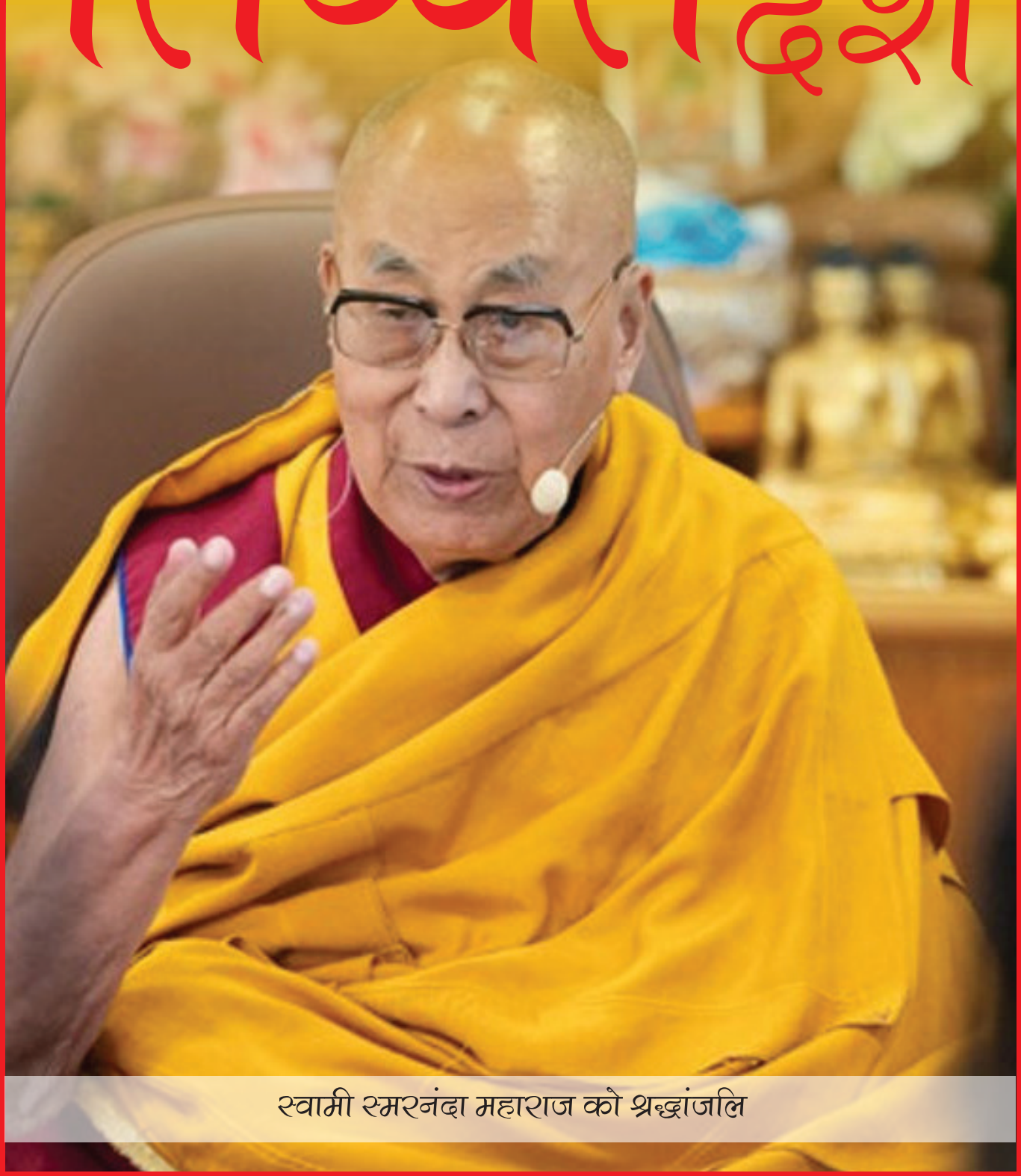

स्वामी स्मरनंदा महाराज को श्रद्धांजलि

मूल्य :10 रू , वार्षिक : 100 रू

मार्च, 2024, वर्ष : 45 अंक : 03

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने मार्टिन लूथर किंग III से मुलाकात की, तिब्बती मुक्ति साधना को लेकर चर्चा की

प्रधान संपादक
ताशी देकि

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
मिग्मार छमचो

वितरण प्रबंधक
नावांग छोडेंन

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

समाचार -

- व्यवहार में करुणा : नेतृत्व के बारे में बातचीत 1
- स्वामी स्मरनंदा महाराज को श्रद्धांजलि 2
- तिब्बत में २०२३ में मानवाधिकार की स्थिति पर रिपोर्ट जारी 3
- **न्यिमा** 4
- **वांगडू** 5
- **केलसांग चोकलांग** 6
- फुंटसोक 7
- रोंग्वो गेंडुन ल्हुंड्रुप 8
- २०२४ के टू सेशन से पता चलता है कि चीन तिब्बत का चीनीकरण की योजना को जारी रखेगा 9
- तिब्बती आवासीय विद्यालय : चीन पर भाषा विनाश की कोशिश का आरोप 10
- संयुक्त राष्ट्र मानावाधिकार प्रमुख का कहना है कि चीन झिंझियांग और तिब्बत में अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है 11
- फ्रीडम हाउस ने तिब्बत को वैश्विक स्तर पर शून्य स्वतंत्रता स्कोर दिया 12
- समुचित प्रतिनिधित्व की कमी : तिब्बतियों को अधिकांश नेतृत्वकारी पदों से अलग रखा गया: २०२४ में पीआरसी नेतृवर्ग में तिब्बती आबादी का प्रतिनिधित्व : एक विश्लेषण 13
- चीन ने डेगे में एक जलविद्युत परियोजना का विरोध कर रहे तिब्बतियों का दमन किया 14
- सीटीए ने तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६५वीं वर्षगांठ मनाई 15

समाचार -

- सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने मार्टिन लूथर किंग III से मुलाकात की, तिब्बती मुक्ति साधना को लेकर चर्चा की 16
- निर्वासित तिब्बती संसद का बजट सत्र शुरू 17
- तिब्बती संसदीय सत्र के दौरान लामा लोबज़ांग के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित 18
- मानवाधिकारों के लिए नियुक्त डच राजदूत तिब्बतियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं और उन्होंने उनकी रिहाई का आह्वान किया है 19
- कैनबरा स्थित तिब्बत कार्यालय ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से चीनी विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान तिब्बत मुद्दे को उठाने का आग्रह किया 20
- अमेरिकी सदन में तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित 21
- यूरोपीय संघ ने तिब्बत में गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की और चैड्रेल रिनपोछे की तत्काल रिहाई का आह्वान किया 22
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ५५वें सत्र में तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठा 23
- जर्मन और ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडलों ने तिब्बतियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की 24
- सम्मेलन का वक्तव्य : तिब्बत समर्थक समूहों का नौवां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 25
- शांति और सद्भाव प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया 26

मुद्रक एवं प्रकाशक
जमयांग दोरजी द्वारा
नोरबू ग्राफ़िक्स , 1/6, बेसमेंट
विक्रम विहार , लाजपत नगर
नई दिल्ली - 110024

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट

coordinator@indiatibet.net

- अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया 27
- ऑस्ट्रेलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया 28
- जर्मनी के हैम्बर्ग राज्य की संसद की सदस्य अन्ना-एलिजाबेथ वॉन ट्रुएनफेल्स-फ्रोवेन ने निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया 29

तिब्बती जनक्रांति दिवस पर राजनीतिक दलों से तिब्बत नीति की मांग

तिब्बती समुदाय तथा तिब्बत समर्थकों द्वारा इस वर्ष भी गत 10 मार्च, 2024 को तिब्बती जनक्रांति दिवस के अवसर पर विभिन्न देषों में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये। इससे चीन का चिंतित होना स्वाभाविक है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में पहली बार 10 मार्च, 1959 को तिब्बतियों ने चीनी अत्याचार के विरोघ में शांतिपूर्ण प्रदर्षन किया था। उसकी याद में वैसे ही विरोध प्रदर्षन प्रतिवर्ष विभिन्न देषों में हो रहे हैं। चीन में साम्यवाद आते ही चीन सरकार ने अपने पड़ोसी देषों में अवैध घुसपैठ शुरू कर दी। इसी के परिणामस्वरूप साम्यवादी चीन का अपने सभी पड़ोसी देषों के साथ सीमा विवाद है। स्वतंत्र तिब्बत के मामले में यही हुआ था।

भारत एवं चीन के बीच तिब्बत एक स्वतंत्र देष (बफर स्टेट) था। चीन की दीवार ही चीन की सीमा थी। चीन की दीवार के बाहर तिब्बत था। चीन सरकार ने सन् 1949 से ही चीन का भूभाग बताते हुए तिब्बत में घुसपैठ प्रारम्भ कर दी। तिब्बत में मानवाधिकारों का हनन बढ़ने लगा। तिब्बती इतिहास तथा धर्म-संस्कृति से जुड़े मठ-मंदिर एवं अन्य संस्थान ध्वस्त हो गये। प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण चीन सरकार की उपनिवेषवादी षड्यंत्रकारी नीति के षिकार हो गये। तिब्बती धर्मगुरु तथा राजप्रमुख परमपावन दलाईलामा का जीवन भी संकट में पड़ गया। ऐसी अमानवीय परिस्थिति में तिब्बतियों ने अपने जीवन को दाँव पर लगाकर ल्हासा में 10 मार्च, 1959 को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्षन किया था। सन् 1949 से 1959 अर्थात् दस वर्ष में ही चीन सरकार ने स्वतंत्र तिब्बत को अपने अवैध नियंत्रण में ले लिया था। उसने दलाईलामा के साथ किये गये समझौते को भी समाप्त कर दिया था।

चीन को पता है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुरूप तिब्बत कभी भी चीन का अंग नहीं था। तिब्बत आजाद जरूर होगा। भ्रम फैलाकर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। तिब्बत यदि चीन का अंग होता तो चीन सरकार वहाँ दमन-उत्पीड़न की नीति नहीं चलाती।

इस वर्ष तिब्बती जनक्रांति दिवस के अवसर पर चीन सरकार की क्रूरतापूर्ण तिब्बत नीति की तीव्र भत्र्सना की गई। चीनी क्रूरता का ही परिणाम है कि पिछले दो-तीन वर्षों में ही डेढ़ सौ से अधिक शांतिप्रिय तिब्बती आंदोलनकारी आत्मदाह कर चुके हैं। शरीर के किसी अंग में मामूली खरोच आने, चोट लगने या तेज धूप से भी भंयकर पीड़ा होती है। हम यथाशीघ्र बचाव के उपाय करते हैं। लेकिन तिब्बती अपने शरीर में अपने हाथों ही आग लगाकर जल रहे हैं। चीनी उत्पीड़न से बचने का यही रास्ता बचा है। दलाईलामा और भारत स्थित निर्वासित तिब्बत सरकार की आंदोलनकारियों से आत्मदाह नहीं करने की अपील के बावजूद ऐसा हो रहा है। तिब्बती संघर्ष में यह सर्वोच्च बलिदान है। आत्मदाह के माध्यम से अपने

जीवन का समर्पण। इस प्रकार के बलिदान से सभी तिब्बती एवं तिब्बत समर्थक चिंतित और विचलित हैं। ऐसे मामले में चीन सरकार का व्यवहार सचमुच निंदनीय है।

आत्मदाह कर चुके आंदोलनकारियों के परिजनों-मित्रों को चीन सरकार विषेष रूप से झुठे मुकदमों में फँसाकर जेल भेज रही है तथा प्रताड़ित कर रही है। जनक्रांति दिवस के अवसर पर प्रामाणिकता के साथ बताया गया कि विकास के नाम पर तिब्बत के पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। प्राकृतिक सम्पत्ति का विनाश हो रहा है। ग्लेसियर्स (हिमनद) की भरमार के कारण संसार की छत, तीसरा ध्रुव तथा वाटर टावर कहलाने वाले तिब्बत में ग्लेसियर्स सूखते-सिकुड़ते जा रहे हैं। इससे तिब्बत के पड़ोसी देषों में जल संकट बढ़ता जा रहा है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा चनाब (प्राचीन नाम असिक्नी तथा चन्द्रभागा) समेत कई नदियाँ तिब्बती ग्लेसियर से निकलकर भारत आती हैं। चीन सरकार इन पर मनमाने ढंग से बांध बनाकर इनके जल-प्रवाह को नियंत्रित कर रही है। इससे भारतीय क्षेत्र चीन की इच्छानुसार बाढ़ एवं सूखे का षिकार होता रहेगा।

तिब्बती पहचान मिटने के कगार पर है। तिब्बती अपने भूभाग में ही संसाधनविहीन तथा अधिकारविहीन हो गये हैं। इस भूभाग का व्यापक पैमाने पर चीनीकरण जारी है। चीनी मूल के लोगों का तिब्बत की सम्पत्ति एवं प्रषासन पर कब्जा है। तिब्बती अपने पारंपरिक उत्सव मनाने तथा दलाईलामा की तस्वीर रखने के अधिकार से वंचित हैं। चीन सरकार दलाईलामा को आतंककारी-विघटनकारी मानती है। स्वतंत्र तिब्बत के राजप्रमुख रहे दलाईलामा शांति के लिये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। वे अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मान-पुरस्कार-उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। वे कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा जनप्रतिनिधि संस्थाओं को संबोधित कर चुके हैं। उनके बारे में अपनी हठधर्मिता छोड़ चीन सरकार उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ पुनः वार्ता प्रारम्भ करे।

हमारे भारतीय राजनीतक दल 2024 के संसदीय चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में तिब्बत संबंधी नीति स्पष्ट करें। भारत की शांति, सुरक्षा, समृद्धि तथा स्वाभिमान की दृष्टि से तिब्बत समस्या का समाधान जरूरी है। हमारे भारतीय समाज में सभी जगह कैलाष एवं मानसरोवर नामक व्यक्ति, संस्थान तथा क्षेत्र मिल जायेंगे। तिब्बत पर अवैध चीनी नियंत्रण के पहले हम भारतीय बेरोकटोक कैलाष-मानसरोवर यात्रा करते थे। अब यह मुष्किल है क्योंकि इसके लिये चीन सरकार भारी शुल्क वसूलती है। इसके साथ ही चीनी प्रषासन यात्रियों की जासूसी करता है। चीन सरकार की साम्राज्यवादी तिब्बत नीति पर अंकुष विष्वजनमत की मांग है। तिब्बत का पड़ोसी होने के कारण भारत अपनी निर्णायक भूमिका निभाये। इसी में भारत का हित है।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राजस्थान)

मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

◆ परम पावन दलाई लामा १) व्यवहार में करुणा : नेतृत्व के बारे में बातचीत

थेकचेन चोएलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। आज सुबह परम पावन दलाई लामा ने दलाई लामा फेलो प्रोग्राम में भाग लेने आए चौदह युवा नेतृत्वकर्ताओं और आमंत्रित अतिथियों से मुलाकात की। दलाई लामा फ़ेलो प्रोग्राम सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने वाले समूहों को प्रशिक्षित करने वाला एक साल का अपूर्व कार्यक्रम है।

◆ २) स्वामी स्मरनंदा महाराज को श्रद्धांजलि

थेकचेन चोएलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। परम पावन दलाईलामा ने आज सुबह राम कृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन को पत्र लिखकर अपने आध्यात्मिक बड़े भाई स्वामी स्मरनंदा महाराज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।

परम पावन ने लिखा, 'मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं रामकृष्ण मिशन के सदस्यों और उनके अनेक अनुयायियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

'मन में यह विचार आने पर सुखद महसूस होता है कि दिवंगत आध्यात्मिक स्वामी ने बहुत ही फलप्रद जीवन जीया और समाज के हित में सेवा के निमित्त अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया।

मैं इस दुखद क्षण में दिवंगत स्वामी जी के अनेक मित्रों और अनुयायियों के साथ खड़ा हूं और अपने बड़े आध्यात्मिक बंधु की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

तिब्बत के अंदर की स्थिति

◆ ३) तिब्बत में २०२३ में मानवाधिकार की स्थिति पर रिपोर्ट जारी

चीन ने हालांकि, अपनी बर्बर जीरो कोविड नीति के नियमों को २०२३ में ही समाप्त कर दिया है, लेकिन उसके नाम पर तिब्बत में रहनेवाले तिब्बतीयों को अब भी अभिव्यक्ति की आजादी, धार्मिक विश्वास और आस्था पर दमनकारी हमले झेलने पड़ रहे हैं। चीन की तिब्बतियों को जबरन आत्मसात करने की नीति को तत्काल रोकने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बार-बार की अपीलों के बावजूद यह जारी है। चीनी प्रशासन तिब्बती स्कूलों में चीनी माध्यम से शिक्षा को लागू कर ही रहा है और तिब्बती क्षेत्रों में मंदारिन चीनी भाषा को प्रसारित करने के लिए स्थाननीय नियमों में संशोधन कर रहा है।

तिब्बतियों को न केवल एकत्र होने की स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित किया जाता है, बल्कि उन्हें दमनकारी और अन्यायपूर्ण सरकारी नीतियों के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से राय या आलोचना व्यक्त करने पर भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है। चीनी अधिकारी सामाजिक स्थिरता बनाए रखने की आड़ में सभी ऑनलाइन प्लेटफार्मों की प्रत्यक्ष निगरानी करते हैं और उन पर सेंसरशिप लागू करते हैं।

तिब्बतियों के धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार को ज्यादा ही कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने धार्मिक स्थलों की स्थापना, प्रबंधन और वहां की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए और अधिक दमनकारी कानून लागू कर दिए हैं। सरकार द्वारा कोविड प्रतिबंधों में ढील दिए जाने का तिब्बती बौद्धों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो तीर्थयात्रा पर पहले से लागू प्रतिबंधों का उसी तरह से सामना करना पड़ रहा है।

तिब्बत के अंदर रहने वाले तिब्बती बंदियों को लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है। मनमाने ढंग से, निवारक तरीके से या बलपूर्वक हिरासत में लिए गए लोगों को अन्यायपूर्ण सजा और यातनाएं दी जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप अनेक बंदियों की हिरासत में मौतें हुईं। राजनीतिक कैदियों को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही अज्ञात स्थानों पर गुप्त हिरासत में रखने का चलन नियमित रूप से बना हुआ है। इससे रिहाई के बाद इन राजनीतिक कैदियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं स्थायी रूप से हो जाती हैं और उनकी असमय मौतें हो जाती हैं। चीन को २०२३ में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से चुना गया। यह संस्था वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख जिम्मेदार निकाय है। चीन का संस्था में फिर से निर्वचित होना दर्शाता है कि चीन जैसे अधिनायकवादी देश किस तरह से व्यवस्थित अभियान चलाकर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को वैश्विक स्तर पर लागू करने की संयुक्त राष्ट्र की क्षमता को कमजोर करते हैं और विश्व संस्था की क्षमता को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रणाली में हेराफेरी के अलावा तरह- तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं।

तिब्बत में चल रहे अन्याय और मानवाधिकारों का उल्लंघन, चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में किए जा रहे मानवाधिकारों के हनन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चीनी सरकार को उन सभी तिब्बतियों को रिहा करना चाहिए जिन्हें केवल अपने मानवाधिकारों और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या सार्वजनिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए हिरासत में रखा गया है।

तिब्बती राजनीतिक कैदियों के बारे में

◆ ४) न्यिमा

गिरफ्तारी की तारीख : जनवरी २०२२
वर्तमान स्थिति: ३ साल की कैद
आरोप: निर्वासित तिब्बतियों से संपर्क

संक्षिप्त परिचय : ०५ जून २०२२ को चीनी अधिकारियों ने एक विश्वविद्यालय छात्र नीमा को 'राष्ट्रीय गोपनीयता को उजागर करने' के मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर तीन साल की जेल की सजा सुनाई। सबसे पहले उन्हें निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों से संपर्क करने का आरोप लगने के बाद जनवरी में खाम कर्ज़े में गिरफ्तार किया गया था। चीनी अधिकारियों ने नीमा के परिवार या दोस्तों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि नीमा ने किस तरह की 'गोपनीयता' को उजागर किया है। नीमा सिचुआन में गेहो नेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और तिब्बती संस्कृति का अध्ययन करते है। वह धाराप्रवाह तिब्बती, चीनी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। उन्हें पर्यटकों और आगंतुकों को तिब्बत की अनूठी भाषा और संस्कृति से बड़ी संजीदगी से अवगत कराने के लिए जाना जाता है। हो सकता है कि इन्हीं कारणों से उनकी गिरफ्तारी की गई हो। नीमा की गिरफ्तारी तिब्बती भाषा और संस्कृति के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के कारण तिब्बती बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी की तरह की ही है।

◆ ५) वांगडू

गिरफ्तारी की तारीख: १४ मार्च २००८
वर्तमान स्थिति : आजीवन कारावास
आरोप: चीन द्वारा मानवाधिकारों के हनन का ढिढोरा पीटना

संक्षिप्त परिचय : चीनी अधिकारियों ने ल्हासा में १० मार्च १९५९ को भड़की तिब्बत जनक्रांति की याद में इसकी वर्षगांठ मनाते हुए १४ मार्च २००८ को भड़के ल्हासा विद्रोह के अवसर पर विरोध-प्रदर्शनों के दौरान मनमाने ढंग से वांगडू को गिरफ्तार कर लिया। २७ अक्तूबर २००८ को 'जासूसी' के झूठे आरोप में ल्हासा इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट द्वारा उन्हें जीवन भर के लिए राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन पर चीनी प्रशासन द्वारा तिब्बती प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किए गए दमन के बारे में जानकारी प्रसारित करने का आरोप लगा। इसके अतिरिक्त उन पर तीन तिब्बती साथियों के साथ मिलकर 'तिब्बती जनक्रांति' समर्थक फ़्लायर्स और सीडी वितरित करने का आरोप लगाया गया था। अतीत में, वह ल्हासा में मार्शल लॉ के खिलाफ विरोध करने पर १९८९ से आठ साल की जेल की सजा काट चुके हैं। उस समय वह जोखांग मंदिर में भिक्षु थे। २०१२ में गवाहों के विवरण से संकेत मिलता है कि उन्हें गंभीर यातना दी गई, एकान्त कारावास में रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप उनका हाथ टूट गया। वांगडू ने ल्हासा में एचआईवी/एड्स रोकथाम परियोजना पर काम किया था और २००१ से तिब्बत में एड्स जागरूकता को बढ़ावा दे रहे थे। उनके परिवार के सदस्यों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। परिवार के लोग उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते रहते हैं।

◆ ६) केलसांग चोकलांग

केल्सांग चोकलांग
गिरफ्तारी की तारीख: २३ नवंबर २०१३
वर्तमान स्थिति: १० साल की कैद
आरोप: तिब्बत के द्रिरू में चीन के खनन का विरोध करना

संक्षिप्त परिचय : चीनी अधिकारियों ने २३ नवंबर २०१३ को केलसांग चोकलांग को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें १० साल की कैद की सजा सुनाई। उन पर तिब्बत के ड्रिरू काउंटी में आर्थिक लाभ के लिए चीन की जनवादी सरकार द्वारा नाजुक पर्यावरण के शोषण की आलोचना करने का आरोप था। जनवरी २०१४ में उन्हें 'भीड़ इकट्ठा करने' के झूठे आरोप में उन्हें ग़लत सज़ा सुनाई गई थी। केलसांग चोकलांग तारमो मठ के भिक्षु हैं और उन्हें तिब्बती संस्कृति से बहुत प्यार और उसका सम्मान करने वाला व्यक्ति माना जाता है। नाग्चू के साचू (चाकू) टाउनशिप के युथांग गांव के मूल निवासी चोकलांग तिब्बती संस्कृति की सुरक्षा और विभिन्न राष्ट्रीयताओं के बीच सद्भाव के प्रबल समर्थक भी हैं। १० अगस्त २०२३ को संयुक्त राष्ट्र के तीन स्वतंत्र विशेषज्ञों ने केलसांग चोकलांग और आठ अन्य तिब्बती पर्यावरण अधिकार रक्षक बंदियो की तत्काल रिहाई की मांग की थी।

◆ ७) फुंटसोक

गिरफ्तारी की तारीख: ५ मार्च, २०२४
वर्तमान स्थिति: मनमाने ढंग से हिरासत
शुल्क: सूचना तिब्बत से बाहर भेजना

चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के लुंड्रब काउंटी से ५ मार्च २०२४ को फुंटसोक को गिरफ्तार कर लिया। उन पर तिब्बत के बाहर दस्तावेज़ भेजने का आरोप लगाया गया। फुंटसोक के परिवार ने उनके ठिकाने और गिरफ्तारी के बारे में जानने के लिए पुलिस स्टेशन से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चीनी अधिकारियों द्वारा फुंटसोक पर कथित तौर पर 'कुछ गोपनीय दस्तावेजों को' तिब्बत के बाहर लीक करने और तिब्बतियों के बारे में पर्याप्त कल्याणकारी योजनाएं चलाने में विफल रहने को लेकर स्थानीय अधिकारियों की खिंचाई करने का आरोप लगाया गया है। फुंटसोक तथाकथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में लुंड्रब (लिनझोउ जियान) काउंटी में सोटो (चीनी: चुंडुई) टाउनशिप के रहने वाले हैं और उनकी १५ साल की बेटी और ११ साल का बेटा है।

◆ ८) रोंग्वो गेंडुन ल्हुंडुप

रोंग्वो गेंडुन ल्हुंडुप
उपनाम: 'ल्हम्क ओक'
गिरफ्तारी की तारीख: ०२ दिसंबर २०२०
स्थिति: चार साल की कैद
आरोप: 'अलगाववाद भड़काना'

संक्षिप्त परिचय: तिब्बत के आमदो प्रांत के रेबगोंग में रोंग्वो मठ के पूर्व भिक्षु गेंडुन ल्हुंडुप को ०२ दिसंबर २०२० को चीनी अधिकारियों द्वारा गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था। उन्हें 'खोरवा' शीर्षक से

कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित करने के तुरंत बाद ०१ दिसंबर २०२१ को ज़िनिंग इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट द्वारा 'अलगाववाद भड़काने' के मनगढ़ंत आरोप में चार साल की सावधि कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उन्हें दो साल के लिए राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। तिब्बती भाषा और संस्कृति के प्रसिद्ध पैरोकार गेंडुन ने कई कविताएं लिखी हैं, जिनमें 'द वन बोर्न इन द पिंग ईयर' और 'खोरवा' आदि शामिल हैं। उनके परिवार द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद चीनी अधिकारियों ने उनकी सज़ा के बारे में जानकारी देने और जेल में उनसे मिलने देने से लगातार इनकार किया है। प्रमुख कवि, आलोचक और तिब्बती संस्कृति के प्रखर समर्थक के रोंग्वो से अतीत में कई मौकों पर पूछताछ की गई और उन्हें हिरासत में भी लिया जा चुका है।

◆ ९) २०२४ के टू सेशन से पता चलता है कि चीन तिब्बत का चीनीकरण की योजना को जारी रखेगा

चीन की हाल ही में संपन्न हुई वार्षिक राजनीतिक बैठकों से यह साफ हो गया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनका प्रशासन चीन को तेजी से वैचारिक राज्य में बदल रहे हैं। इसके अलावा शी तिब्बती बौद्ध धर्म के साथ-साथ तिब्बती जीवन के अन्य सभी पहलुओं का 'चीनीकरण' करने की अपनी योजना को जारी रखे हुए हैं। चीन में इस बैठक को दो 'टू सेशन' कहा जाता है।

तिब्बत को लेकर राष्ट्रीय नेताओं का मत

इस वर्ष ०४ मार्च से ११ मार्च के बीच आयोजित चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) और चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (सीपीपीसीसी) की वार्षिक बैठकों में चीनी नेताओं ने एकमत से उस दृष्टिकोण का समर्थन किया जो विचारधारा को लोगों की ज़िंदगी के अन्य सभी पहलुओं से ऊपर रखता है। बैठक में चीन के शीर्ष नेतृत्व का तिब्बत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ध्यान आया। इन सबका यही मत था कि तिब्बती पहचान को चीनी पहचान में बदलने की योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

सीपीपीसीसी के अध्यक्ष वांग हुनिंग ने ०४ मार्च, २०२४ को पेश अपनी रिपोर्ट में तिब्बत का सीधा उल्लेख किया। पिछले साल सीपीपीसीसी के काम को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट के पांचवें बिंदु में वांग ने कहा, 'नए युग में तिब्बत और झिंझियांग पर शासन करने के लिए पार्टी की रणनीति का अध्ययन किया और उसे कार्यान्वित किया। इसके लिए १० शोध किए गए। इसके साथ ही तिब्बती बौद्ध धर्म और झिंजियांग में इस्लाम का चीनीकरण करनेको बढ़ावा देने के लिए तिब्बत, झिंझियांग और सिचुआन प्रांत स्थित तिब्बती आबादी वाले काउंटियों में निरीक्षण किया गया। वहां पर विभिन्न नस्लीय समूहों के बीच मेलमिलाप और एकीकरण को मजबूत किया गया। इतिहास की व्याख्या, प्रचार, शिक्षण का काम हुआ और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में चीनी राष्ट्र समुदाय की जागरूकता शिक्षा पर गहन शोध को मजबूत किया गया।

रिपोर्ट में तिब्बती बौद्ध धर्म का उल्लेख असल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के २०१७ में आयोजित १९वीं पार्टी कांग्रेस में तिब्बती बौद्ध धर्म सहित सभी धर्मों के चीनीकरण के आह्वान और उसके बाद २०१९ में सरकार समर्थित चीन बौद्ध एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई बौद्ध धर्म के चीनीकरण की पंचवर्षीय योजना के अनुरूप किया गया है। चीनीकरण का तात्पर्य गैर-चीनी समूहों को चीनी संस्कृति में आत्मसात करने और सीसीपी के प्रति वफादार बनने के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया से है। शी जिनपिंग ने २०१८ में धार्मिक नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कुख्यात यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट (यूएफडब्ल्यूडी) को प्रभारी बनाकर पार्टी शासित प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन किए। सीसीपी के एक बड़े विभाग को राज्य प्रशासन, खासकर अनुशासन निरीक्षण मामले में ऊपर रखना हाल ही में कई नीति क्षेत्रों में एक नियमित घटना रही है।

०८ मार्च, २०२४ को एनपीसी को अपनी रिपोर्ट में अध्यक्ष झाओ लेजी ने २०२३ में पारित 'किंघई-तिब्बत पठार के पारिस्थितिक संरक्षण पर कानून' का उल्लेख किया, जो 'किंघई-तिब्बत पठार' के पारिस्थितिकीय संरक्षण और सतत विकास के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है। झाओ ने कहा, 'हमने संबंधित पक्षों को प्रासंगिक मानक दस्तावेजों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया।' झाओ ने यह भी उल्लेख किया कि इस वर्ष वे क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता पर कानून की ४०वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक संगोष्ठी आयोजित करेंगे। यह कानून ०१ अक्तूबर, १९८४ को लागू हुआ था और यह कथित तौर पर तिब्बतियों और 'नस्लीय अल्पसंख्यक'माने जाने वाले अन्य समुदायों को अधिकार प्रदान करता है।'

चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने ०५ मार्च, २०२४ को एनपीसी को दी गई अपनी कार्य रिपोर्ट में तिब्बत का सीधा उल्लेख नहीं किया। हालांकि, रिपोर्ट में ऐसी योजनाएं शामिल थीं जो तिब्बती लोगों को प्रभावित करनेवाला है। ली ने कहा, 'हम विकास में तेजी लाने, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को मजबूत करने, विकास को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों में जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पुराने क्रांतिकारी आधार क्षेत्रों और बड़ी जातीय अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों का समर्थन करेंगे।' तिब्बत में विकास को बढ़ावा देने के इस कार्यक्रम का एक राजनीतिक एजेंडा है और इसमें ग्रामीण पुनरोद्धार की पहल शामिल है जिसका मुख्य अर्थ है- याक और भेड़ का वध तेजी से करना। चीन में २०१८ में तेजी से फैलने वाला वायरल संक्रमण शुरू हुआ था और इसके परिणामस्वरूप लगभग आधे सूअरों की मौत हो गई थी। ये मौतें या तो बीमारी से हुईं या वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से सूअरों को मारने से हुईं। चूंकि चीन को मांस आपूर्ति को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता थी, और राजनीतिक कारणों से अमेरिका

तथा अन्य सूअर मांस आयात करनेवाले देशों के एजेंडे से बाहर होने के कारण तिब्बत से निर्यात का एकमात्र साधन याक मांस रह गया है। इस प्रक्रिया को ग्रामीण पुनरुद्धार को बढ़ावा देने की रणनीति के अंतर्गत रखा गया।

ली ने कहा, 'हम चीनी राष्ट्र के लिए समुदाय की मजबूत भावना पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय नस्लीय स्वायत्तता की प्रणाली को बनाए रखेंगे और उसमें सुधार करेंगे। सभी नस्लीय समूहों के बीच बातचीत, आदान-प्रदान और एकीकरण को बढ़ावा देंगे और नस्लीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आधुनिकीकरण अभियान को गति देंगे।'

तिब्बती बौद्ध धर्म का चीनीकरण करने के सीसीपी के इरादे की पुष्टि करते हुए ली ने यह भी कहा, 'हम धार्मिक मामलों पर पार्टी की मूल नीति का पालन करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि चीन में धर्मों का विकास चीनीकरण की तर्ज पर होना चाहिए और धर्मों को चीनी नीति के आधार पर मार्गदर्शन किया जाएगा ताकि उन धर्मों को चीनी संस्कृति और हमारे समाजवादी समाज के अनुकूल किया जा सके।'

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एनपीसी और सीपीपीसीसी दोनों के पूर्ण सत्र को संबोधित नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधिमंडलों की बैठकों को संबोधित किया। हालांकि उनमें से कोई भी तिब्बती नहीं था। २०२१ में 'टू सेशन (दो सत्रों)' के दौरान शी ने किंघई प्रतिनिधिमंडल के विचार-विमर्श में भाग लिया और यहां तक कि २०१० के भूकंप के बाद युशू की अपनी यात्रा को भी याद किया।

◆ १०) तिब्बती आवासीय विद्यालय : चीन पर भाषा विनाश की कोशिश का आरोप

तिब्बती शैक्षिक समाजशास्त्री ग्याल लो मंदारिन- चीनी धाराप्रवाह बोल सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहेंगे।

उन्होंने पिछले कुछ साल तक बीजिंग द्वारा तिब्बती क्षेत्रों में किए गए व्यापक शैक्षिक सुधारों के बारे में दुनिया को बताते रहे हैं लेकिन वह तिब्बतियों का औपनिवेशिक उत्पीडन करनेवाले चीन की भाषा का उपयोग करना कभी पसंद नहीं करेंगे।

चीन ने चार साल की उम्र के तिब्बती बच्चों को आवासीय स्कूलों में अनिवार्य भर्ती की नीति चला रखी है और हाल में इसका विस्तार किया है। साथ ही शिक्षण की मुख्य भाषा के तौर पर तिब्बती की जगह चीनी को अनिवार्य किया है।

बीजिंग का कहना है कि चूंकि चीन में संवाद और संचार की मुख्य भाषा चीनी है, इसलिए इस तरह के सुधार तिब्बती बच्चों को उनके आगामी जीवन के लिए संभावित सभी प्रकार से सर्वोत्तम स्तर की तैयारी में मदद कराने वाले हैं।

लेकिन डॉ. ग्याल लो इससे असहमत हैं। उनका मानना है कि बीजिंग का असली उद्देश्य समाज में बच्चों में संस्कार बदलकर तिब्बती पहचान को कमजोर करना है।

उन्होंने कहा, 'चीन सरकार ने ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया है जो एक ऐसी पीढी तैयार करेगा जो भविष्य में अपनी भाषा और संस्कृति से जुडने में सक्षम नहीं होगी।'

'चीन तिब्बतियों की सामाजिक क्षमता को कम करने के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है। इससे कोई भी उनके शासन का विरोध नहीं कर पाएगा।'

विदेशी मानवाधिकार संगठन दशकों से तिब्बत में चीन द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवहारों को उजागर करते रहे हैं - लेकिन हाल के वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है। चीन के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र झिंझियांग में मुस्लिम उइगरों के साथ बीजिंग के व्यवहार और हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन पर ध्यान केंद्रित हो गया है। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि चीनी अधिकारी तिब्बत में भी बर्बरता कर रहे हैं।

हाल के वर्षों में चीनी सरकार ने गांव के स्कूलों और तिब्बती भाषा पढ़ाने वाले निजी स्कूलों को बंद कर दिया है और बोर्डिंग स्कूलों का विस्तार किया है। ये बहुत कम आबादी वाले कई चीनी क्षेत्रों में कई दशकों से चलन में हैं। लेकिन तिब्बती क्षेत्रों में ये शिक्षा के मुख्य साधन बन गए हैं।

कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि ८०% तिब्बती बच्चों- शायद दस लाख विद्यार्थियों- को अब स्कूल जाने की उम्र से कम आयु में ही बोर्डिंग स्कूलों में डाल दिया जाता है।

बीबीसी को दिए एक बयान में लंदन स्थित चीनी दूतावास ने कहा कि यह नीति ज़रूरी था। बयान में कहा गया है, 'बहुत दूर दूर बसी आबादी के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो बहुत असुविधाजनक है। अगर हर जगह स्कूल बनाए जाते हैं तो पर्याप्त शिक्षक और शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होगा।' इसीलिए स्थानीय सरकारें बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही हैं। लेकिन विरोधियों का कहना है कि इस तरह की स्कूली शिक्षा उन बच्चों और परिवारों पर मनोवैज्ञानिक आघात पैदा करती है जिन्हें जबरन अपने परिवारों से अलग कर दिया जाता है और अपने बच्चों को दूर भेजने के लिए दबाव डाला जाता है।

१० साल की होने के पहले कई वर्षों तक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर चुकी एक तिब्बती किशोरी ने कहा, 'मेरे जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू

अपने परिवार को याद करना था।'

वह तब से तिब्बत से भागी हुई है और भारत में रहती है। बीबीसी ने एक अभियान समूह के माध्यम से संपर्क करने के बाद उनसे बात की। उन्होंने कहा, 'ऐसे कई अन्य बच्चे भी थे जो अपने परिवार को याद करते थे और रोते भी थे। कुछ छोटे बच्चे अक्सर आधी रात में रोते हुए उठ जाते थे और स्कूल के गेट की ओर भागते थे।'

◆ ११) संयुक्त राष्ट्र मानावाधिकार प्रमुख का कहना है कि चीन झिंझियांग और तिब्बत में अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है

जिनेवा, ०४ मार्च (रायटर्स)। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने सोमवार को चीन से झिंझियांग और तिब्बत क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों में संशोधन करने की सिफारिशों को लागू करने का आह्वान किया।

इन अधिकार समूहों ने बीजिंग पर उइगरों के साथ भारी दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम नस्ल के अल्पसंख्यक हैं। इनकी संख्या झिंझियांग के पश्चिमी क्षेत्र में लगभग एक करोड है। इसमें से बडी संख्या में उइगरों से जबरन श्रम शिविरों में काम कराया जाता है। हालांकि बीजिंग किसी भी प्रकार के बर्बर और सख्त दुर्व्यवहार से इनकार करता है।

तुर्क ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को बताया, 'मैं सरकार से झिंझियांग और तिब्बत क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों, नीतियों और प्रथाओं के संबंध में अपने जिनेवा कार्यालय और अन्य मानवाधिकार निकायों द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने का भी आह्वान करता हूं।'

◆ १२) फ्रीडम हाउस ने तिब्बत को वैश्विक स्तर पर शून्य स्वतंत्रता स्कोर दिया

निगरानी समूह- फ्रीडम हाउस ने अपनी नई 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड' रिपोर्ट में कहा है कि ६५ वर्षों के चीनी कब्जे के बाद तिब्बत का वैश्विक स्वतंत्रता स्कोर अब शून्य तक गिर गया है।

'इंटरनेशनल कंपेन फॉर तिब्बत' के अध्यक्ष तेनचो ग्यात्सो ने कहा, 'इस स्कोर से अब कोई संदेह नहीं रह जाता है कि तिब्बत पर चीन का कब्ज़ा एक वैश्विक हादसा है। चीनी सरकार ने ६५ वर्षों तक तिब्बत पर इस हद तक क्रूरता की है कि उसका वैश्विक स्वतंत्रता स्कोर अब निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह तिब्बत में चीन की विफल नीतियों का स्पष्ट आरोप है और इस विनाशकारी कब्जे को हल करने के लिए चीनी सरकार को तिब्बती नेताओं के साथ शांतिपूर्ण बातचीत शुरू करने की आवश्यकता है।

फ्रीडम हाउस की २९ फरवरी को जारी २०२४ की रिपोर्ट में तिब्बत का राजनीतिक अधिकार स्कोर संभावित ४० में से नकारात्मक ०२ है और नागरिक स्वतंत्रता स्कोर संभावित ६० में से केवल ०२ है। इससे तिब्बत को १०० में से कुल मिलाकर ० का स्कोर मिलता है।

तिब्बत की शून्य रेटिंग कम से कम आठ वर्षों में सबसे खराब है। फ्रीडम हाउस की २०२३ रिपोर्ट में तिब्बत का कुल स्कोर ०१ रहा है।

◆ १३) समुचित प्रतिनिधित्व की कमी : तिब्बतियों को अधिकांश नेतृत्वकारी पदों से अलग रखा गया

२०२४ में पीआरसी नेतृवर्ग में तिब्बती आबादी का प्रतिनिधित्व : एक विश्लेषण

चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (संसद) और चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (राजनीतिक सलाहकार निकाय) की वार्षिक बैठकों का दौर चल है। लोकप्रिय रूप से से 'टू सेशन (दो सत्र)' कहा जाता है। चीन इन सत्रों का इस्तेमाल यह प्रचारित करने के लिए भी कर रहा है कि तिब्बती और अन्य नस्लीय अल्पसंख्यक लोग अपने अधिकारों का कितनी अच्छी तरह से उपभोग कर रहे हैं।

यह दावा दिसंबर २०२३ में एक चीनी राजनयिक द्वारा दोहराया गया था। उन्होंने दावा किया था कि 'चीन में अल्पसंख्याक ५६ नस्लीय समूह अपनी कम आबादी की परवाह किए बिना समान रूप से रह रहे हैं और राष्ट्रीय मामलों में समान रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं।' अगस्त २०२१ में चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (सीपीपीसीसी) के तत्कालीन अध्यक्ष वांग यांग ने 'तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति की ७०वीं वर्षगांठ मनाने वाली बैठक' में भाग लेने के लिए तिब्बती राजधानी ल्हासा की अपनी यात्रा के दौरान दावा किया कि 'मुक्ति' के बाद 'तिब्बत (इसका अर्थ है तिब्बत देश पर चीन का अधिपत्य) में लाखों किसानों का उद्भव हुआ और उनका भविष्य उनके अपने ही हाथों में आ गया।'

चीन का दावा है कि तिब्बत का उसके द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद से तिब्बती लोग 'खुद अपना भाग्य विधाता' बन गए हैं।

यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर और तिब्बती क्षेत्रों में प्रांतीय और उप-प्रांतीय स्तरों पर वर्तमान नेतृवर्ग में प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करती है और निष्कर्ष स्वरूप बताती है कि तिब्बतियों के पास मुख्य रूप से सांकेतिक पद हैं जबकि तिब्बत में वास्तविक शक्ति गैर-तिब्बतियों के हाथों में बनी हुई है। :

'इंटरनेशनल कंपेन फॉर तिब्बत' ने इस परिस्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'यह सही तथ्य है कि कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत में तिब्बतियों को असली नेतृत्वकारी पदों पर नियुक्त नहीं करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी नेतृत्व तिब्बतियों पर इस बात के लिए भरोसा नहीं करता है कि वे सीसीपी शासन का समर्थन करेंगे। उल्टे यदि उनके पास इस शासन के विरोधी शासन का विकल्प होता और यदि अब भी संभव हुआ तो तिब्बती लोग सीसीपी शासन को ख़त्म करने में नहीं हिचकिचाएंगे।'

चीनी शासन प्रणाली के तीन अंग माने जाते हैं- चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी), सेना और सरकार। इनमें सरकार और सेना कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन हैं। पार्टी के भीतर इसका संचालन करनेवाले तीन महत्वपूर्ण अंग हैं- केंद्रीय समिति, पोलित ब्यूरो और पोलित ब्यूरो स्थायी समिति। इसमें स्थायी समिति सबसे शक्तिशाली होती है। प्रशासन के राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रीफेक्चुरल स्तरों पर इन सभी विभिन्न अंगों में तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व जिस स्तर पर है, वह तिब्बतियों के मामले में चीन के शासन की भेदभावपूर्ण नीति का संकेत करता है।

निर्वासन में जाने से पहले चीनी शासन के तहत तिब्बत में जीवन का अनुभव कर चुके तिब्बती विद्वान दावा नोरबू ने १९७८ में लिखा कि तिब्बती लोग अपने उपर चीनी कब्जे को कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा, चीन का कहना रहा है कि 'तिब्बत में चीनी मिशन प्रगति के एक नए युग की शुरुआत है, जिसमें पूर्व-औद्योगिक या पुरातन पंथी लोगों के लिए नए चमत्कारों के संकेत दिए गए थे। चीनियों का कहना था कि जैसे ही तिब्बत के लोग स्वयं शासन करने योग्य हो जाएंगे, चीनी लोग वहां से लौट जाएंगे।' इस तरह से चीनी शासन द्वारा तिब्बतियों के लिए स्वायत्तता नामक एक अजूबे अवधारणा को परिभाषित किया गया था।

२०२४ में तिब्बत में तिब्बतियों की स्थिति को देखने से पता चलता है कि वे अपना भविष्य अपने हाथों में रखने के बजाय, अपनी ही मातृभूमि में दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं। २०२० में हमने चीनी शासन में तिब्बतियों के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि आबादी की दृष्टि से तिब्बतियों के पास कुछ स्तर का प्रतिनिधित्व है लेकिन व्यवहार में सारी शक्ति गैर-तिब्बतियों, मुख्य रूप से चीनियों के हाथों में है। चार साल बाद वर्तमान में भी प्रीफेक्चुरल और काउंटी स्तर पर तिब्बती प्रतिनिधित्व के मामले में यह स्थिति वैसी ही बनी हुई है।

पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तहत तिब्बत को १७ प्रीफेक्चुरल- और दो काउंटी-स्तरीय (गैर-तिब्बती प्रीफेक्चर के तहत) प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित किया गया है। इनमें तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (इसके अंतर्गत सात प्रीफेक्चुरल स्तर के क्षेत्र), सिचुआन प्रांत के अंतर्गत दो प्रीफेक्चुरल-स्तरीय और एक काउंटी क्षेत्र, किंघई प्रांत के अंतर्गत छह प्रीफेक्चुरल-स्तरीय क्षेत्र, गांसु प्रांत के अंतर्गत एक प्रीफेक्चुरल और एक काउंटी स्तर का क्षेत्र और युन्नान प्रांत में एक प्रीफेक्चुरल स्तरीय क्षेत्र हैं।

◆ १४) चीन ने डेगे में एक जलविद्युत परियोजना का विरोध कर रहे तिब्बतियों का दमन किया

गत १४ फरवरी को सिचुआन प्रांत में गार्जे तिब्बती स्वायत्त प्रान्त के तहत डर्ज काउंटी (मंदारिन में डेगे) में सैकड़ों तिब्बतियों ने काउंटी सरकारी कार्यालय भवन के सामने विरोध-प्रदर्शन किया। तिब्बती लोग ड्रिचु नदी पर बन रहे ११ लाख किलोवाट के जलविद्युत स्टेशन के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि अधिकारी ऊपरी वोंटो और शिपा गांवों और छह महत्वपूर्ण मठों से हजारों तिब्बतियों को स्थानांतरित करने के आदेश को वापस लें - जिसमें वोंटो मठ भी शामिल है, जो १३ वीं शताब्दी में बनाया गया था और उस काल के बेशकीमती भित्तिचित्र हैं। बांध का जलाशय पूरा होने पर गांवों और मठों में बाढ़ आने की आशंका है।

स्थानीय तिब्बतियों का कहना है कि इस जलविद्युत परियोजना ने इन मठों की पवित्र प्रकृति और मठों से संचालित तिब्बती बौद्धों की संस्कृति, धर्म और मूल्य प्रणाली के महत्व को नजरअंदाज कर दिया है। डर्ज़े उस तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, जिसकी सीमाएं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा खींची गई हैं। बल्कि डर्जे ऐतिहासिक तिब्बती क्षेत्र खाम का हिस्सा है।

१४ फरवरी के बाद से जलविद्युत परियोजना के खिलाफ कई अहिंसक विरोध- प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि, सरकार की सख्ती से इन प्रदर्शनों को दबाया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने अनेक भिक्षुओं सहित १००० से अधिक तिब्बतियों को गिरफ्तार किया है और इन मठों पर पूर्ण रूप से ताला लगा दिया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में से कुछ दर्जन लोगों को आगे से विरोध- प्रदर्शनों में भाग न लेने के सख्त निर्देशों के साथ रिहा कर दिया गया है। हिरासत में रहने के दौरान वोंटो मठ के वरिष्ठ प्रशासक और एक ग्राम अधिकारी सहित कई अन्य लोगों को कथित तौर पर 'बुरी तरह से पीटे जाने' के बाद एक बड़े हिरासत केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था।

गंगटुओ (कामटोक) जलविद्युत परियोजना ड्रिचू नदी

पर नियोजित १३ जलविद्युत स्टेशनों की शृंखला में से एक है, जिसे मंदारिन में जिंशा नदी के रूप में जाना जाता है। इसे 'हुआडियन जिंशा रिवर अपर रीचेज हाइड्रोपावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड' द्वारा बनाया जा रहा है। इसका नियंत्रण और संचालन वर्तमान में सीधे चीन-हुआडियन ग्रुप द्वारा किया जाता है।

नवंबर २०११ में राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग ने संबंधित राष्ट्रीय मंत्रालयों और आयोगों के अलावा सिचुआन, तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र और किंघई की प्रांतीय सरकारों के साथ मिलकर ड्रिचु नदी की ऊपरी पहुंच की जलविद्युत परियोजना को लेकर तैयार रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने गंगटुओ पर प्रमुख जलाशय के रूप में 'एक जलाशय और तेरह स्तर' बनाने पर सहमति व्यक्त की। जलविद्युत परियोजना की व्यावहारिक संभावना के बारे में अध्ययन २०१६ में पूरा हो गया था। डैम अब चीन की १३वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया जा रहा है। २२९ मीटर का बांध यांग्त्ज़ी से पीली नदी की ओर पानी मोड़ने के लिए दक्षिण-से-उत्तर जल मोड़ परियोजना (साउथ टू नार्थ वाटर डिवीजन प्रोजेक्ट) के पश्चिमी मार्ग के लिए प्रमुख जलाशय भी है। इस तरह से तिब्बत की कभी प्राचीन और मुक्त बहने वाली नदियों को अब तेजी से बनाए जा रहे जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की नवीनतम गतिविधियां

◆ १५) सीटीए ने तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६५वीं वर्षगांठ मनाई

धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के अधिकारी और कर्मचारी गण धर्मशाला में तिब्बती तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६५वीं वर्षगांठ मनाने के लिए १० मार्च २०२४ को सुगलगखांग के प्रांगण में एकत्र हुए। यह एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में दर्ज है जो तिब्बत पर चीनी कब्जे के खिलाफ तिब्बतियों के प्रतिरोध को दर्शाता है। जनक्रांति के दौरान दुखद परिणाम के रूप में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की शहादत हो गई थी।

उन शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम में जर्मन सांसद माइकल कार्ल ब्रांड के अलावा ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर डीन एंथोनी स्मिथ, सीनेटर डेबोरा मैरी ओ'नील, सांसद माइकल मैककॉर्मैक, सांसद डेविड स्मिथ से गठित एक ऑस्ट्रेलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल, सीटीए का नेतृवर्ग, उसके विभिन्न विभागों के सचिवों, सीटीए कर्मचारियों, अनुभाग प्रमुखों, गैर सरकारी संगठनों के प्रमुखों और आम जनता ने भी भाग लिया।

कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर शुरुआत सिक्योंग द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। इसके साथ ही तिब्बती इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के कलाकारों द्वारा तिब्बती राष्ट्रगान गाया गया।

स्पीकर खेनपो सोनम तेनफेल और सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने क्रमशः निर्वासित तिब्बती संसद और काशाग के वक्तव्य पढ़े।

मुख्य अतिथि जर्मन सांसद माइकल कार्ल ब्रांड ने पूर्व में विभाजित जर्मनी और सीसीपी शासन के तहत तिब्बतियों के बीच समानता का उल्लेख किया और जर्मनी की तरह तिब्बतियों के पुनर्मिलन की आशा व्यक्त की।

ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर डेबोरा मैरी ओ'नील ने सभी के लिए स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए तिब्बतियों के साथ अपनी एकजुटता को अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'हम जिस शांति की उम्मीद करते हैं, वह मूल रूप से स्वतंत्रता की गारंटी पर आधारित है, यह दोनों तरह की स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता का पर आधारित है। इसमें आपके लोगों की सोचने, बोलने, गाने, नृत्य करने और अपने इतिहास को अपने लोगों की भाषा में लिखित रूप में बताने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।' उन्होंने सभा को आश्वासन दिया कि ऑस्ट्रेलियाई लोग तिब्बत में तिब्बतियों की चिंताओं के लिए अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे।

इसी तरह, सीनेटर डीन एंथोनी स्मिथ, सांसद माइकल मैककॉर्मैक और सांसद डेविड स्मिथ ने एकत्रित तिब्बतियों की तालियों और सराहना के बीच तिब्बती मुद्दे के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। समारोह का समापन शहीदों के लिए प्रार्थनाओं के पाठ के साथ हुआ।

◆ १६) सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने मार्टिन लूथर किंग III से मुलाकात की, तिब्बती मुक्ति साधना को लेकर चर्चा की

धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने काशाग सचिवालय में वैश्विक मानवाधिकार कार्यकर्ता और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बेटे मार्टिन लूथर किंग III और दलाई लामा केंद्र के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

बैठक के दौरान सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने तिब्बत के राजनीतिक इतिहास, तिब्बत के अंदर की स्थितियों और निर्वासित तिब्बती समुदाय को लेकर सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। तिब्बती मुक्ति साधना पर प्रकाश डालने के लिए सिक्योंग ने तिब्बत-चीन और तिब्बत-भारत के बीच प्राचीन संबंधों का दृष्टांत दिया और पीआरसी द्वारा तिब्बत पर किए जा रहे इस दावे को खारिज कर दिया कि तिब्बत प्राचीन काल से ही चीन का अभिन्न अंग है। इसके साथ ही सिक्योंग ने तिब्बत-चीन संघर्ष को हल करने लिए तिब्बत को ऐतिहासिक रूप से सिद्ध एक अलग इकाई के रूप में बनाए रखते हुए

मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के तरीके को अपनाने पर जोर दिया।

सिक्योंग ने तिब्बत के अंदर की स्थितियों पर प्रकाश डाला। उनकी चर्चा में विशेष रूप से बीजिंग द्वारा तिब्बत की नदी प्रणाली के शोषण और दुरुपयोग के कारण बिगड़ते पर्यावरण, तिब्बत की विशिष्ट पहचान को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने, चीनी सरकार द्वारा तिब्बती धर्म को अपनी संस्कृति में विलय कर देने, उच्च लामाओं के पुनर्जन्म को मान्यता देने की प्रणाली में हेरफेर करने और तिब्बत के अंदर कठोर निगरानी का विस्तार करने की बातें सामने आईं।' । सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने आगे निर्वासित तिब्बती समुदाय और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारियों के बारे में उन्हें जानकारी दीं।

मार्टिन लूथर किंग III ने सुबह में परम पावन दलाईलामा से विशेष मुलाकात की। सिक्योंग के साथ बैठक के दौरान किंग ने मानवता की एकता को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका स्थित दलाईलामा केंद्र के साथ सहयोग करने में अपनी रुचि प्रकट की।

◆ १७) निर्वासित तिब्बती संसद का बजट सत्र शुरू

धर्मशाला। वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिए १७वीं निर्वासित तिब्बती संसद का सातवां सत्र (बजट सत्र) १८ से ३० मार्च तक चलेगा। आज १८ मार्च की सुबह ९:३० बजे स्पीकर की सत्र शुरुआत की घोषणा के साथ बजट-सत्र शुरू हुआ।

सबसे पहले निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर खेनपो सोनम तेनफेल और डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग, मंत्रियों और सांसदों ने सदन में एकत्रित होकर तिब्बती राष्ट्रगान गाया। इसके बाद स्पीकर के भाषण और कार्यवाहक अध्यक्षों और तदर्थ समिति के सदस्यों की नियुक्ति के साथ सत्र शुरू हुआ।

सदन को संबोधित करते हुए स्पीकर ने तिब्बत के उचित मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए चीन में वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को समझने के महत्व पर जोर दिया। परम पावन दलाई लामा के परोपकारी कार्यों के माध्यम से चीन-तिब्बती संघर्ष को मिली वैश्विक मान्यता को देखते हुए कार्रवाई करने का महत्वपूर्ण यह अवसर माना गया।

स्पीकर ने निर्वासित तिब्बती संसद की स्थापना को लंबे समय से परम पावन दलाई लामा की आकांक्षा होने पर प्रकाश डालते हुए सत्र का एजेंडा पेश किया। इसमें बजट की प्रस्तुति, नियम और विनियमन समीक्षा समिति की रिपोर्ट, बजट अनुमान समिति की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक मामले शामिल थे। अध्यक्ष ने सांसदों को अपने विचार-विमर्श के दौरान परम पावन के दृष्टिकोण और आकांक्षाओं पर विचार करने की सलाह दी।

सांसद गेशे ल्हारम्पा गोवो लोबसांग फेंडे द्वारा तिब्बत के अंदर की गंभीर परिस्थितियों पर एकजुटता जताने वाला आधिकारिक प्रस्ताव पेश किया गया और सांसद गेशे अतोंग रिनचेन ग्यालत्सेन द्वारा उसका समर्थन किया गया।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के निवर्तमान वित्त कालोन (वित्त मंत्री) सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का २०२४-२५ बजट पेश किया, जिसमें ३३३१५.५ लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा गया।

निर्वासित तिब्बती संसद की बजट अनुमान समिति के अध्यक्ष सांसद गेशे ल्हारम्पा गोवो लोबसांग फेंडे ने समिति की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के २०२४-२५ बजट पर चर्चा की शुरुआत सांसद तेनजिन जिगदल की और सांसद छेरिंग यांगचेन ने इसका समर्थन किया।

आज के सत्र में बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. क्लेमेंस अर्ज़ट पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे, जहां सदन द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

◆ १८) तिब्बती संसदीय सत्र के दौरान लामा लोबज़ांग के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित

धर्मशाला। १७वीं निर्वासित तिब्बती संसद के चल रहे सातवें सत्र (बजट सत्र) ने अपने दूसरे दिन के पहले सत्र के दौरान आज सुबह एक प्रसिद्ध हिमालयी बौद्ध गुरु और प्रखर तिब्बत समर्थक वेन लामा लोबजांग के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया। जोबजांग ने अपनी जीवन भर की सेवाएं मानवीय सहायता के लिए समर्पित कर दीं थीं।

तिब्बती सांसद गेशे न्गावा गांगरी द्वारा प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में उन्होंने दिवंगत लामा लोबज़ंग की एक संक्षिप्त जीवनी भी पढ़ी। प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद १७वीं निर्वासित तिब्बती संसद और १६वीं कशाग (कैबिनेट) के सदस्यों ने शोक में एक मिनट का मौन रखा।

लद्दाख के लेह में जन्मे वेन लामा लोबजांग ने चिकित्सा देखभाल और अन्य सहायता उपायों के माध्यम से अपना अधिकांश जीवन तिब्बतियों सहित अन्य लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने विभिन्न पदों पर कई सार्वजनिक कार्यालयों और गैर-लाभकारी संगठनों में भी काम किया, जिनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (भारत सरकार) के सदस्य, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के अध्यक्ष और अशोक मिशन, महरौली के अध्यक्ष सहित अन्य अहम पद शामिल हैं।

१९) मानवाधिकारों के लिए नियुक्त डच राजदूत तिब्बतियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं और उन्होंने उनकी रिहाई का आह्वान किया है

ब्रुसेल्स। मानवाधिकारों के लिए नियुक्त डच राजदूत विम गीर्ट्स ने १४ मार्च २०२४ को पूर्वी तिब्बत के डर्जे में छह मठों और दो गांवों के ध्वंस कर देने वाले डैम के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे तिब्बतियों की सामूहिक गिरफ्तारी की रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

अपने ट्वीट में राजदूत गीर्ट्स ने चीन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करने पर गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई का आह्वान किया और इस अधिकार को बनाए रखने के अपने देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

२०) कैनबरा स्थित तिब्बत कार्यालय ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से चीनी विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान तिब्बत मुद्दे को उठाने का आग्रह किया

कैनबरा। इस सप्ताह चीनी विदेश मंत्री वांग यी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले अति आवश्यक आवेदन देकर वहां के तिब्बती प्रतिनिधि कर्मा सिंगे ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से तिब्बत में गंभीर स्थिति पर चर्चा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है।

अपने पत्र में चीनी शासन के तहत तिब्बतियों द्वारा सामना किए जा रहे दमनकारी कार्रवाइयों और प्रणालीगत भेदभाव पर प्रकाश डालते हुए प्रतिनिधि ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान देने और तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री को संबोधित अपने पत्र में प्रतिनिधि कर्मा सिंगे ने कहा है कि वांग यी की आगामी आस्ट्रेलिया यात्रा तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति के बारे में चिंताओं को उठाने का महत्वपूर्ण अवसर है।

पत्र में विभिन्न उल्लंघनों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग करना और सरकार द्वारा संचालित बोर्डिंग स्कूलों में उन्हें चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा पढ़ने को मजबूर करना शामिल है। इसके अतिरिक्त पत्र धार्मिक रिवाजों पर लगाए गए गंभीर प्रतिबंधों, तिब्बती भिक्षुओं और व्यक्तियों की मनमानी हिरासत और डर्जे काउंटी में तिब्बत के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हालिया कार्रवाई पर प्रकाश डालता है।

चीन को उसके मानवाधिकारों के हनन के लिए जवाबदेह ठहराने के महत्व पर जोर देते हुए, प्रतिनिधि ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से आग्रह किया कि वह इन गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए चीन के साथ अपने राजनयिक जुड़ाव का उपयोग करे।

ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री और वांग यी के बीच नियोजित बैठक के दौरान प्रतिनिधि ने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करने का आग्रह किया है :

१. तिब्बत मुद्दे और यहां के मानवाधिकार संकट, जिसमें राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का चल रहा दमन, पर्यावरणीय गिरावट और तिब्बती सांस्कृतिक और भाषा का उन्मूलन शामिल है।

२. चीनी सरकार से आग्रह करें कि वह डर्ज काउंटी में उन सभी तिब्बती प्रदर्शनकारियों को तुरंत और बिना शर्त रिहा करे, जिन्हें शांतिपूर्ण विरोध के अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है। इस दौरान घायल तिब्बतियों के लिए उचित और समय पर चिकित्सा उपचार सुनिश्चित किया जाए।

३. चीन को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के तिब्बत में आने-जाने की अनुमति और तिब्बत में मीडिया और आवागमन की अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित करें।

४. चीन-तिब्बत वार्ता को फिर से शुरू कराकर तिब्बत मुद्दे को हल करने के लिए चीन को वास्तव में प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करें। चूंकि ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ महत्वपूर्ण व्यापार संबंध बनाए रखता है, इसलिए प्रतिनिधि ने दोनों देशों के बीच अधिक न्यायसंगत और उचित संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय चर्चाओं में मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया।

तिब्बत मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन

◆ २१) अमेरिकी सदन में तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित

अमेरिका प्रतिनिधि सभा में द्विदलीय एकजुटता प्रदर्शित करते हुए मैसाच्यूचेट्स से डेमोक्रेट प्रतिनिधि जेम्स पी. मैकगवर्न कैलिफोर्निया से रिपब्लिकन प्रतिनिधि यंग किम ने १० मार्च को ६५वें तिब्बती जनक्रांति दिवस पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में तिब्बत में चीनी सरकार द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के बीच तिब्बती लोगों के पक्ष में समर्थन की पुष्टि की गई।

प्रस्ताव एच. आरईएस १०७२ तिब्बती लोगों के स्थायी संघर्ष को मान्यता प्रदान करता है और चीन की सैन्य आक्रामकता के कारण परम पावन १४वें दलाई लामा के तिब्बत से भागने की ६५वीं वर्षगांठ को अधिकृत करता है। यह तिब्बती आत्मनिर्णय के लिए समर्थन की पुष्टि करता है और अनिवार्य रूप से सरकार संचालित बोर्डिंग स्कूलों की औपनिवेशिक नीतियों, तिब्बती खानाबदोशों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) द्वारा तिब्बती लोगों की विशिष्ट धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को व्यवस्थित रूप से मिटाने और तिब्बती लोगों की धार्मिक रिवाजों में सरकार के हस्तक्षेप की निंदा करता है।

प्रस्ताव में पूर्वी तिब्बत के डेर्जे में एक जलविद्युत डैम के निर्माण और डैम निर्माण परियोजना का विरोध करने वाले १००० से अधिक तिब्बतियों की सामूहिक गिरफ्तारी और हिरासत की कड़ी निंदा की गई है। इस कार्रवाई से स्थानीय समुदायों और ऐतिहासिक स्थलों पर इसके विनाशकारी प्रभाव के कारण व्यापक आक्रोश फैल गया है। प्रस्ताव डैम निर्माण परियोजना के कारण तिब्बतियों के विस्थापन और ऐतिहासिक मठों के विनाश के साथ-साथ प्रदर्शनकारियों की मनमानी हिरासत पर चिंता व्यक्त करता है। प्रस्ताव में चीन के सभी कैदियों की तत्काल रिहाई की मांग की गई है, जिसमें डर्जे डैम का विरोध करने के कारण हिरासत में लिए गए तिब्बती भी शामिल हैं और बिडेन प्रशासन से चीन पर तिब्बत के डर्जे में डैम परियोजना को रोकने के लिए दबाव डालने का आह्वान किया गया है।

प्रतिनिधि मैकगवर्न ने प्रस्ताव के महत्व पर जोर देते हुए कहा, '६५ साल हो गए हैं जब परम पावन १४वें दलाई लामा को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया था। तब से हर दिन तिब्बती लोग अपने मानवाधिकारों और अपने आत्मनिर्णय के लिए लड़ रहे हैं। पीआरसी को अपने कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का पालन करना चाहिए और तिब्बतियों पर अत्याचार करना बंद करना चाहिए।' प्रस्ताव में पीआरसी को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करने और तिब्बतियों पर अत्याचार बंद करने की सलाह दी गई है।

प्रतिनिधि किम ने प्रस्ताव की द्विदलीय प्रकृति पर जोर दिया और स्वतंत्रता और सम्मान की तलाश में तिब्बती लोगों का समर्थन करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। किम ने कहा, 'तिब्बती लोगों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दशकों तक उत्पीड़न सहा है। यह जरूरी है कि हम उनके साथ खड़े हों और सीसीपी को उसके गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराएं।'

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग कहते हैं, 'मैं चीन के उत्पीड़न के खिलाफ तिब्बती लोगों के प्रतिरोध के समर्थन में ६५वें तिब्बती जनक्रांति दिवस के अवसर पर इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए प्रतिनिधि जिम मैकगवर्न और प्रतिनिधि किम यंग के प्रति अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहता हूं। हम तिब्बत-चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देने वाले अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।'१७वीं निर्वासित तिब्बती संसद के चल रहे सातवें सत्र (बजट सत्र) ने अपने दूसरे दिन के पहले सत्र के दौरान आज सुबह एक प्रसिद्ध हिमालयी बौद्ध गुरु और प्रखर तिब्बत समर्थक वेन लामा लोबजांग के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया। जोबजांग ने अपनी जीवन भर की सेवाएं मानवीय सहायता के लिए समर्पित कर दीं थीं।

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग कहते हैं, 'मैं चीन के उत्पीड़न के खिलाफ तिब्बती लोगों के प्रतिरोध के समर्थन में ६५वें तिब्बती जनक्रांति दिवस के अवसर पर इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए प्रतिनिधि जिम मैकगवर्न और प्रतिनिधि किम यंग के प्रति अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहता हूं। हम तिब्बत-चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देने वाले अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।'

◆ २२) यूरोपीय संघ ने तिब्बत में गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की और चैड्रेल रिनपोछे की तत्काल रिहाई का आह्वान किया

ब्रुसेल्स। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ५५वें सत्र के दौरान आइटम- ४ के तहत एक बयान में यूरोपीय संघ ने तिब्बत में गंभीर मानवाधिकार स्थिति के बारे में अपनी चिंताओं को दोहराया। इसमें मुख्य रूप से चीन सरकार द्वारा संचालित आवासीय स्कूलों में तिब्बती बच्चों को जबरन शामिल करने और तिब्बतियों के डीएनए नमूनों का सामूहिक संग्रह पर प्रकाश डाला गया है।

इसके अलावा यूरोपीय संघ ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, पत्रकारों, स्वतंत्र पत्रकारों, अन्य मीडिया कर्मियों, शिक्षाविदों, लेखकों और बुद्धिजीवियों द्वारा झेले जा रहे अंतरराष्ट्रीय दमन, उत्पीड़न, धमकी, निगरानी पर प्रकाश डाला है। यूरोपीय संघ ने तिब्बतियों के बाहर जाने पर प्रतिबंध, घर में नजरबंदी, यातना, दुर्व्यवहार, गैरकानूनी हिरासत, सजा और जबरन गायब कर दिए जाने की कड़ी निंदा की, जिसमें एक निर्दिष्ट स्थान (आरएसडीएल) में आवासीय निगरानी भी शामिल है, जो यातना और दुर्व्यवहार की श्रेणी में आ सकता है।

अपने बयान में यूरोपीय संघ ने चीन से तिब्बतियों सहित सभी राष्ट्रीयताओं वाले समूहों के मानवाधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और उन्हें पूरा करने के लिए खुद चीन के संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत दायित्वों का पालन करने का आग्रह किया। यूरोपीय संघ ने कानून के शासन और पुन:पूर्ति के सिद्धांत का सम्मान करने और किसी भी ऐसी बाहरी गतिविधि (जबरदस्ती सहित) से परहेज करने के महत्व पर जोर दिया जो अंतरराष्ट्रीय कानून के विरूद्ध है।

इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ ने स्थिति की बारीकी से निगरानी करने की अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया और चैड्रेल रिनपोछे, अने सेंगद्रा, गो शेरब ग्यात्सो, गोलोग पाल्डेन, ताशी दोरजे, ज़ंगकर जामयांग और सेमकी डोल्मा सहित अन्य तिब्बती कार्यकर्ताओं की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया।

तिब्बत में गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करने वाले

यूरोपीय संघ के बयान का स्वागत करते हुए ब्रुसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि जेनखांग ने पहली बार व्यक्तिगत मामलों की सूची में गोलोग पाल्डेन, सेमकी डोल्मा, ज़ंगकर जामयांग और विशेष रूप से चैड्रेल रिनपोछे को शामिल करने और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करने के लिए यूरोपीय संघ के प्रति आभार व्यक्त किया।

यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपरोक्त चार राजनीतिक कैदी हाल ही में ब्रुसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत मामलों की सूची का हिस्सा थे।

◆ २३) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ५५वें सत्र में तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठा

जिनेवा। एक तिब्बती प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से चीन के मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टों पर तुरंत ध्यान देने का आग्रह किया।

जिनेवा स्थित तिब्बत ब्यूरो में संयुक्त राष्ट्र एडवोकेसी अधिकारी फुंटसोक टोपग्याल ने २० मार्च २०२४ को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ५५वें सत्र के दौरान एक मौखिक बयान दिया, जिसमें तत्काल ध्यान देने की मांग करने वाले महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने तिब्बती सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के चीन के व्यवस्थित प्रयासों पर भी चिंता व्यक्त की।

टोपग्याल ने पिछले छह दशकों से तिब्बती लोगों के अधिकारों के घोर उल्लंघन पर प्रकाश डालते हुए तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति की ६५वीं वर्षगांठ के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इन दुरुपयोगों को रोकने के लिए परिषद से तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया। टोपग्याल ने आवासीय विद्यालयों में लगभग १० लाख तिब्बती बच्चों के नामांकन, तिब्बतियों के आंखों की स्कैनिंग और डीएनए संग्रह सहित चीन द्वारा किए जा रहे व्यापक निगरानी उपायों के साथ ही ११वें पंचेन लामा गेदुन चोएक्यी न्यिमा के लापता होने जैसी अनसुलझी चिंताओं का हवाला दिया और तिब्बत में गंभीर स्थिति को रेखांकित किया। ११वें पंचेन लामा गेदुन चोएक्यी न्यिमा अगर जीवित हुए तो इस वर्ष ३५ वर्ष की आयु के हो जाएंगे।

हाल की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए टोपग्याल ने कहा कि मानवाधिकार परिषद के ५५वें सत्र से ठीक चार दिन पहले चीनी अधिकारियों ने डर्ज में एक बड़े डैम के निर्माण का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे तिब्बतियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कीं। इस डैम परियोजना से दो गांवों के विस्थापित होने, बौद्ध मठों और प्राचीन भित्तिचित्रों के नष्ट होने का खतरा है।

टोपग्याल ने चीन से सभी तिब्बती प्रदर्शनकारियों को बिना शर्त रिहा करने और डैम परियोजना को रोकने का आग्रह किया, जो तिब्बती पठार के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भीषण खतरा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से आह्वान किया कि वह चीन से मांग करे कि चीनी सरकार गोनपो जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने और उनके खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई करने से परहेज करे और उनकी स्वतंत्रता के अधिकार को बरकरार रखे।

◆ २४) जर्मन और ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडलों ने तिब्बतियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की

धर्मशाला। धर्मशाला में ६५वें तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस के आधिकारिक स्मरणोत्सव में भाग लेने वाले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने तिब्बत के अंदर पीआरसी द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और तिब्बती मुद्दे पर अपनी चिंताओं को प्रकट करने और इसके लिए अपना प्रतिबद्ध समर्थन व्यक्त करने के लिए आज शाम को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया।

इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन संसद में 'पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत' के अध्यक्ष सांसद माइकल ब्रांड, सीनेटर डीन स्मिथ, ऑस्ट्रेलियाई संसद में ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत (लिबरल पार्टी) के सह-अध्यक्ष सांसद माइकल मैककॉर्मैक, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री (नेशनल पार्टी) सीनेटर डेबोरा ओ'नील और सांसद डेविड स्मिथ (लेबर पार्टी) ने भाग लिया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले वक्ता के तौर पर बोलते हुए सांसद माइकल ब्रांड ने कहा, 'एक ओर सभ्य दुनिया तिब्बत और उसकी प्राचीन और अनूठी सभ्यता और संस्कृति के साथ खड़ी है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आधार पर परिभाषित नरसंहार को देखें तो बीजिंग तिब्बतियों और उइगरों के खिलाफ नरसंहार अभियान चला रहा है। चीन का और भी अधिक दमनकारी और अधिक आक्रामक नेतृत्व न केवल तिब्बत के लिए बल्कि एशिया और उससे आगे पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की आक्रामक विदेश नीतियों और उसके दमनकारी घरेलू कार्यों की निंदा करते हुए लंबे समय से निर्वाचित हो रहे जर्मन सांसद ने समान विचारधारा वाले उन देशों से संयुक्त प्रयासों का आह्वान किया, जो आक्रामक नेताओं को युद्ध का सहारा लेने से रोकने' के लिए 'सभ्य अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' कायम करने के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा, 'यही कारण है कि तिब्बत न केवल तिब्बत के लोगों के लिए बल्कि एशिया, भारत और अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था के लिए बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करने, आत्मनिर्णय का सम्मान करने और सरकारों से गैर-आक्रामक और गैर-दमनकारी व्यवहार का अनुरोध करने के लिए इतना महत्वपूर्ण है।'

ऑस्ट्रेलियाई ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत के सह-अध्यक्ष सीनेटर डीन स्मिथ ने अपने संबोधन में ऑस्ट्रेलियाई संसद में तिब्बती मुद्दों पर एक स्वर में बात करने वाले इस ऑस्ट्रेलियाई संसदीय समूह के महत्व को रेखांकित किया। सीनेटर ने ऑस्ट्रेलियाई ऑल-पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियाई संसद में तिब्बतियों के मानवाधिकारों पर लगातार हो रहे हमलों' के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उल्लेख किया। इसके साथ ही पिछले जनवरी में चीन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की चौथी सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा में तिब्बती मुद्दे पर आवाज उठाने में इसकी भूमिका को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलियाई लिबरल पार्टी के सीनेटर ने तिब्बती जनक्रांति दिवस के स्मरणोत्सव में भाग लेने और एकजुटता के साथ बयान देने का अवसर मिलने पर अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हुए कहा, 'ऑस्ट्रेलिया में हमें तिब्बतियों के काम से बहुत समर्थन मिलता है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना नया घर बनाया है। हम दृढ़ता से स्वीकार करते हैं कि जब तिब्बती समुदाय ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में मजबूत होता है तो यह लोकतंत्र और मानवता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य में ही होता है और इससे तिब्बत में अधिकारों को प्राप्त की दिशा को और आसान और सरल बनाता है।'

सीनेटर डेबोरा ओ'नील ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जनवरी सत्र के दौरान ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी बयान पढ़ा। उन्होंने बयान को उद्धृत किया, 'ऑस्ट्रेलिया झिंझियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) और तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता और भाषाई स्वतंत्रता के दमन पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर गहराई से चिंतित है। ऑस्ट्रेलिया चीन की आत्मसात करने की नीतियों का विवरण वाली रिपोर्टों को सुनकर बहुत चिंतित हैं। इन रिपोर्टों में श्रमिकों का जबरन स्थानांतरण कार्यक्रम और सरकारी आवासीय स्कूलों के माध्यम से तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग करने का विवरण शामिल है। चीन इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कर रहा है और क्या चीन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त और विशेष प्रक्रिया जनादेश धारकों सहित स्वतंत्र मानवाधिकार पर्यवेक्षकों को झिंझियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) और तिब्बत तक सार्थक और निर्बाध आवागमन की अनुमति देने को तैयार है? उन्होंने आगे कहा, 'हम इस तरह के सवाल पूछेंगी और जब आप जवाब मांगेंगे तो हम आपके साथ एकजुटता से खड़ी रहूंगी।'

सीनेटर डेबोरा ओ'नील के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री सांसद माइकल मैककॉर्मैक ने कहा कि तिब्बती जनक्रांति के बाद ६५ साल का लंबा समय बीत चुका है और आज भी तिब्बतियों के लिए दुःखद समय है, क्योंकि वे अनावश्यक रूप से खोई गई जानमाल की याद करते हैं।' तिब्बती आज उन हजारों शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने तिब्बतियों की आजादी की मुहिम को बढ़ाने के प्रयासों में अपनी जान दे दी। वे केवल इतना चाह रहे थे कि कि उन्हें वह मिल जाना चाहिए जो उनका है। अपने देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के होने और उनके राजनीतिक रुख में मतभेद होने के बावजूद सांसद माइकल मैककॉर्मैक ने पुष्टि की कि इस बार धर्मशाला का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य 'तिब्बत और उस स्वतंत्रता पर सहमत हैं जो तिब्बत ने अर्जित की है और वह जिसके हकदार हैं। ऑस्ट्रेलियाई संसद और पूरे ऑस्ट्रेलिया के लोग तिब्बत और उसकी स्वतंत्रता की ओर से बोलने में इस समूह का निरंतर समर्थन करते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शरण चाहने वाले तिब्बतियों का स्वागत किया और जोर दिया कि, 'हम चाहते हैं कि तिब्बत स्वतंत्र हो, हम वास्तव में चाहते हैं कि भाषा, नृत्य, संगीत, संस्कृति, इतिहास और तिब्बत से जुड़ी हर चीज़ न केवल जीवित रहे बल्कि भविष्य में भी विकसित हो।'

ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी के सांसद डेविड स्मिथ ने अपने संबोधन में अपने प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों की टिप्पणियों को दोहराया। साथ ही सदस्यों की विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद तिब्बती मुद्दे के समर्थन में उनकी एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'हम यहां तिब्बत के अंदर के और निर्वासन में रहे रहे तिब्बती लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं और जैसा कि मेरे सहयोगी सीनेटर ओ'नील ने कहा, 'हम जो कहना चाहते हैं वही बातें स्वतंत्र मानवाधिकार पर्यवेक्षकों की भी राय है।'

दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के संबोधन के बाद मीडिया कर्मियों के साथ एक प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म की मान्यता के अधिकार का चीन द्वारा दुरुपयोग करने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। सदस्यों ने इस संदर्भ में अमेरिका द्वारा पारित कानून का हवाला देते हुए इसी तरह के विधेयकों को अपने-अपने देश की संसदों में पेश करने और पारित करने की संभावना के प्रति आश्वस्त किया। इसके साथ ही सदस्यों ने आज सुबह परम पावन दलाई लामा से मुलाकात के अपने अनुभवों को मीडियाकर्मियों के बीच साझा किया।

◆ २५) सम्मेलन का वक्तव्य : तिब्बत समर्थक समूहों का नौवां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

धर्मशाला। तिब्बत समर्थक समूहों (टीएसजी) का नौवां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यूरोपीय संघ की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के ४० देशों के १७० से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन के वक्तव्य में कहा गया है:-

२०१९ में धर्मशाला में टीएसजी की पिछले सम्मेलन के बाद से हमने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए चीन को एक खतरे के तौर पर देखने में व्यापक समझ बनते देखी है। इसके बाद से तिब्बत-चीन संघर्ष को हल करने के पक्ष में राजनीतिक पक्षधरता के अवसर बढ़ गए हैं। इस लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हुए सम्मेलन के प्रतिभागियों ने अभियान की जीत और हासिल किए गए मील के पत्थर का जश्न मनाया। इनमें से कई की पहचान २०१९ की धर्मशाला कार्ययोजना में प्राथमिक लक्ष्य के रूप में पहचाना गया। इनमें प्रमुख हैं- अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा द्विदलीय यानि सर्वसम्मत संकल्प से 'तिब्बत अधिनियम- २०२४' पारित होना, २०२३ में यूरोपीय संसद के प्रस्ताव में तिब्बत में दमनकारी औपनिवेशिक

आवासीय स्कूल प्रणाली को तत्काल समाप्त करने का आह्वान, २०२४ में चीन की संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) में तिब्बत के लिए बोलने वाली सरकारों की संख्या में दोगुनी वृद्धि, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख समितियों और विशेष दूतों की ओर से तिब्बत में रिवाजों की चिंता और चीन की नीतियों की निंदा करते हुए बढ़ते बयान, चीन के २०२२ शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार, दुनिया भर में सैकड़ों कन्फ्यूशियस संस्थानों को बंद करना, प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में पीआरसी-प्रायोजित प्रचार प्रविष्टियों को रद्द करना और थर्मो-फिशर द्वारा तिब्बत में डीएनए परीक्षण किट की बिक्री बंद करने का हालिया निर्णय आदि।

सम्मेलन ने हिंसक संघर्षों से बेहद आहत दुनिया में परम पावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए दशकों लंबे संघर्ष में तिब्बती लोगों की अहिंसा और लोकतंत्र के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के प्रति अपना सम्मान और प्रशंसा व्यक्त की।

प्रतिभागियों ने इस बात को लेकर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि तिब्बत-चीन संघर्ष को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा पहली प्राथमिकता के तौर पर अहिंसात्मक तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए चाहिए। प्रतिभागियों ने तिब्बतियों के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों के साथ रणनीतिक सहयोग के स्तर को बढ़ाकर इस लक्ष्य के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता की घोषणा की। इनमें पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिणी मंगोलिया, हांगकांग और ताइवान के बहादुर आंदोलनकारियों के साथ ही मानवाधिकार और लोकतंत्र के अनगिनत चीनी रक्षक, विशेष रूप से श्वेत पत्र क्रांति (व्हाइट पेपर रिवॉल्यूशन) से प्रेरित चीनी कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का इजहार किया गया।

सम्मेलन में दुनिया भर के टीएसजी के विविध कौशल, अनुभव और दृष्टिकोण के साथ-साथ सामान्य उद्देश्य की भावना को भी शामिल किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वालों में कई ऐसे व्यक्ति थे जो १९८७ में तिब्बत में विरोध प्रदर्शनों के बाद से तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और अब यूरोप, अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में कुशल और समर्पित तिब्बती कार्यकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने और मार्गदर्शन देने में मदद कर रहे हैं। इस सम्मेलन में दर्जनों सक्रिय युवाओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिणी मंगोलिया, हांगकांग और ताइवान की ओर से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की भागीदारी का स्वागत किया गया और स्वतंत्रता और न्याय के सामान्य लक्ष्य के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई।

उपस्थित लोगों ने सम्मेलन में परम पावन दलाई लामा के संदेश से प्रेरणा ग्रहण की। परम पावन के संदेश में उनका यह बयान भी शामिल था कि, 'मैं हमेशा मानता हूं कि हमारे समर्थक तिब्बत समर्थक नहीं हैं, बल्कि न्याय समर्थक हैं। वह टीएसजी के लिए प्रेरणा हैं और हमेशा रहेंगे।'

ब्रुसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिगज़िन जेनखांग ने सम्मेलन में आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। सम्मेलन में यूरोपीय संसद के तिब्बत हित समूह के अध्यक्ष मिकुलस पेक्सा और यूरोपीय संसद के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हंस गर्ट पॉटरिंग के साथ-साथ निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर खेनपो सोनम तेनफेल, फ्रांसीसी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत के सीनेटर यूस्टाचे-ब्रिनियो और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग की कालोन नॉरज़िन डोल्मा की टिप्पणियों को भी सुना गया।

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने अपने मुख्य भाषण में तिब्बती इतिहास पर चीन के झूठे कथानकों का मुकाबला करने और मध्यम मार्ग नीति में मूल्य जोड़ने के लिए एक स्वतंत्र देश के रूप में तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति पर जोर देने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए मध्यम मार्ग नीति के प्रति केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई।

सम्मेलन में तिब्बत में मानवाधिकारों के दमन का विवरण देने वाले विवरण को गंभीर चिंता के साथ सुना गया। सम्मेलन में चीनी सरकार द्वारा औपनिवेशिक तरीके के आवासीय स्कूलों की प्रणाली के माध्यम से तिब्बत की विशिष्ट राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के व्यवस्थित प्रयास पर प्रकाश डाला गया। इन स्कूलों में चार साल की उम्र के लगभग तीन-चौथाई तिब्बती बच्चों को उनके माता-पिता से छीन लिया जाता है और उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति में शिक्षित होने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है।

सम्मेलन में तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने के चल रहे प्रयासों की निंदा की गई, जिसमें पुनर्जन्म को मान्यता देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का चीन का दुःप्रयास भी शामिल है। सम्मेलन ने दोहराया कि अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार स्वयं तिब्बती लोगों के पास है। केवल परम पावन दलाई लामा और जिन लोगों को वह सौंपते हैं, उन्हें ही उनके पुनर्जन्म को मान्यता देने की प्रक्रिया तय करने का अधिकार है।

सम्मेलन ११वें पंचेन लामा सहित सभी तिब्बती राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की मांग करता है। पंचेन लामा को छह साल की उम्र में चीनी अधिकारियों द्वारा जबरन गायब कर दिया गया था। यह सम्मेलन मानवाधिकारों के पक्ष में बोलने वाले सभी तिब्बतियों की हिरासत और दुर्व्यवहार की निंदा करता है, जिसमें गोंपो क्यी का हालिया मामला भी शामिल है।

सम्मेलन ने हाल के दिनों में प्रस्तावित डैम का शांतिपूर्ण विरोध करने पर डेगे में १००० से अधिक तिब्बतियों की अवैध हिरासत पर चिंता व्यक्त की। इस डैम के निर्माण से दो तिब्बती गांवों का जबरन विस्थापन होगा और कई मठ नष्ट हो जाएंगे। सम्मेलन में इस आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोगों की तत्काल रिहाई, ग्रामीण तिब्बतियों के सभी जबरन स्थानांतरण को समाप्त करने का आह्वान किया गया।

सम्मेलन तिब्बत के नाजुक और महत्वपूर्ण पर्यावरण पर चीन की नीतियों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में गहराई से चिंतित है, विशेष रूप से एशिया की नदियों को बांधने, विनाशकारी खनन प्रथाएं और खानाबदोशों की जबरन बसावट- ये सभी तिब्बती पठार पर जलवायु संकट और पर्यावरण विनाश को बढ़ाते हैं। सबसे अधिक आशंका क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने की है। सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तिब्बत के नाजुक और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण पर्यावरण की भलाई और अखंडता के प्रति अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को पहचानने का आह्वान करता है।

सम्मेलन तिब्बती लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए दुनिया भर की सरकारों की निजी और संयुक्त घोषणाओं की सराहना करता है और उनका स्वागत करता है। सम्मेलन उन सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों का आभारी है जो तिब्बती लोगों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों को पूरा करने और तिब्बत-चीन संघर्ष के लाभकारी समाधान के लिए परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए चीनी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं।

सम्मेलन के प्रतिभागियों ने तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और उनके मानवाधिकारों के सम्मान और तिब्बती पठार के अनूठे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके संघर्ष में समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जब तक कि कोई ऐसा समाधान प्राप्त नहीं हो जाता जो तिब्बतियों के लिए संतोषजनक हो।

सम्मेलन मानवता और तिब्बती लोगों की भलाई के लिए परम पावन के आजीवन योगदान को उजागर करने और शांति, अहिंसा और करुणा के उनके संदेश को फैलाने के लिए उनके कद के अनुरूप गतिविधियों के साथ २०२५ में परम पावन दलाई लामा का ९०वां जन्मदिन मनाने के लिए भी उत्सुक है।

२६) शांति और सद्भाव प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया

धर्मशाला। निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग ने २१ मार्च, २०२४ को अखिल भारत रचनात्मक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विभूति कुमार मिश्रा के नेतृत्व में शांति और सद्भाव के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को निर्वासित तिब्बती संसद की संरचना, विकास और उसके कामकाज की व्यापक जानकारी दी गई।

डिप्टी स्पीकर ने शांति और सद्भाव प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान वैश्विक संघर्षों और पर्यावरणीय गिरावट के बढ़ते दौर में दुनिया भर में शांति, सद्भाव और स्थिरता को बढ़ावा देने में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

तिब्बत में गंभीर पर्यावरणीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए डिप्टी स्पीकर ने न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि मानवता और पर्यावरण के बीच भी सद्भाव की अनिवार्यता के महत्व पर पर प्रकाश डाला। साथ ही तिब्बती पठार के अनियंत्रित दोहन और तिब्बत के पर्यावरण और भारत सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की ओर बहने वाली इसकी नदियों के भीषण विनाश पर प्रकाश डाला। उन्होंने आने वाले मेहमानों से चीन-तिब्बती संघर्ष को हल करने करने के पक्ष में अभियान चलाने, भविष्य के प्रयासों में तिब्बत के पर्यावरण के महत्व को बढ़ाने और समाज के उत्थान में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने का आग्रह किया।

दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल को चल रहे सत्र की कार्यवाही का अवलोकन करने का अवसर मिला, जहां संसद द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

श्री विभूति कुमार मिश्रा नई दिल्ली में अखिल भारत रचनात्मक समाज (एबीआरएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता राज्यसभा की पूर्व सांसद पद्म विभूषण डॉ. निर्मला देशपांडे द्वारा स्थापित संगठन का उद्देश्य विश्व स्तर पर शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।

श्री विभूति कुमार मिश्रा ने परम पावन दलाई लामा की जयंती ०६ जुलाई, २०२३ के शुभ दिन से देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान के साथ शुरू होने वाली एक साल की शांति और सद्भाव यात्रा की शुरुआत की। वह अखिल भारत रचनात्मक समाज के माध्यम से तिब्बती हित में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।

संगठन सामाजिक रूप से वंचित युवाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन का संस्थापक भी है। यह फाउंडेशन ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर हाशिये पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समर्पित है।

◆ २७) अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया

धर्मशाला। अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संघ (आईपीआरए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने ११ मार्च २०२४ को निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में आईपीआरए के महासचिव प्रोफेसर मैट मेयर, सह-महासचिव मारिया थेरेसा मुनोज (अर्जेंटीना), कार्यकारी समिति की सदस्य और लैटिन अमेरिका शांति अनुसंधान परिषद (कोलंबिया) की महासचिव डायना मार्सेला अगुडेलो-ऑर्टिज, अफ्रीका पीस रिसर्च एंड एजुकेशन एसोसिएशन (बुरुंडी/यूएसए) की सदस्य और कुलपति इलावी नदुरा और एशिया-पैसिफिक पीस रिसर्च एसोसिएशन (यूएसए) के सदस्य रॉय तमाशिरो शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर स्पीकर खेनपो सोनम तेनफेल और डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग के साथ चर्चा की।

बैठक के दौरान आईपीआरए प्रतिनिधिमंडल ने अपने संघ, अनुसंधान कार्यक्रमों और तिब्बती संघर्ष के बारे में अपनी समझ के बारे में अपने अनुभव और समझ को व्यक्त किया। उन्होंने दौरे को लेकरऔर निर्वासित संसद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से मिलने को लेकर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

डिप्टी स्पीकर ने परम पावन दलाई लामा द्वारा तिब्बती लोगों को लोकतंत्र का उपहार देने के साथ तिब्बती राजनीति के लोकतंत्रीकरण की व्याख्या करते हुए निर्वासित तिब्बती संसद की संरचना और कार्यप्रणाली का

परिचय दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि परम पावन ने १९६४ की शुरुआत में तिब्बती संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण प्रदान किया था और निर्वासित तिब्बती संसद की एकसदनीय प्रकृति और पार्टी-रहित प्रणाली की व्याख्या की।

'दुनिया की छत' और 'एशिया के जल मीनार' के रूप में तिब्बत के महत्व पर जोर देते हुए डिप्टी स्पीकर तेखांग ने चीन के साथ ही इसमें शामिल देशों से जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने और तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने का आग्रह किया।

अंत में डिप्टी स्पीकर तेखांग ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसी) द्वारा तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाली पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की नीतियों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर उनके प्रभाव पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने आईपीआरए से तिब्बती पठार को लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान करने का भी आह्वान किया।

स्पीकर खेनपो सोनम तेनफेल ने प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करने पर खुशी व्यक्त की और दुनिया की सर्वोपरि जरूरतों में से एक को संबोधित करने के रूप में आईपीआरए के काम की सराहना की।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने निर्वासित तिब्बती संसद का अवलोकन करने, इसके विवरण के बारे में जानने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया और अपने समर्थन का आश्वासन देते हुए तिब्बती मुद्दे के प्रति अपनी एकजुटता का इजहार किया।

◆ २८) ऑस्ट्रेलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया

धर्मशाला। ऑस्ट्रेलिया के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने ११ मार्च २०२४ को निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल जर्मन संसद में पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत के अध्यक्ष सांसद माइकल ब्रांड, ऑस्ट्रेलियाई ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत (लिबरल पार्टी) के सह-अध्यक्ष सीनेटर डीन स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री (नेशनल पार्टी) सांसद माइकल मैककॉर्मैक, सीनेटर डेबोरा ओ'नील तथा लेबर पार्टी की सांसद डेविड स्मिथ ने माइकल मैककॉर्मैक की पत्नी कैथरीन मैककॉर्मैक, ओओटी कैनबरा में तिब्बती प्रतिनिधि कर्मा सिंगे और ऑस्ट्रेलिया तिब्बत काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी ज़ो बेडफोर्ड के साथ निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया।

◆ २९) जर्मनी के हैम्बर्ग राज्य की संसद की सदस्य अन्ना-एलिजाबेथ वॉन ट्रुएनफेल्स-फ्रोवेन ने निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया

धर्मशाला। निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग ने २३ मार्च २०२४ को जर्मनी के हैम्बर्ग राज्य की संसद की सदस्य अन्ना-एलिजाबेथ वॉन ट्रुएनफेल्स-फ्रोवेन के साथ बैठक की। बैठक में फ्रोवेन के पति और दिल्ली स्थित फ्रेडरिक नौमान फाउंडेशन के दो स्टाफ सदस्य शामिल थे। आगत अतिथियों को निर्वासित तिब्बती संसद के विकास, कार्यप्रणाली और संरचना के बारे में जानकारी दी गई।

डिप्टी स्पीकर से मुलाकात के दौरान उन्हें चीनी कब्जे वाले तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। ब्रीफिंग में ड्रिचु नदी पर डैम निर्माण के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए खाम डेगे में १००० से अधिक लोगों की सामूहिक गिरफ्तारी पर प्रकाश डाला गया। ज्ञात है कि यह उैम गांवों और मठों को वहां से विस्थापित कर देगा। इसके अतिरिक्त, तिब्बतियों के जबरन डीएनए संग्रह, औपनिवेशिक तरह के आवासीय स्कूलों में नन्हें तिब्बती बच्चों को भर्ती कर उनके मनोवैज्ञानिक स्थिति का उल्लंघन करने और तिब्बती पहचान को उनकी यादों से मिटाने समेत कई अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं।

डिप्टी स्पीकर ने इस बात पर जोर दिया कि जर्मनी सहित पश्चिम के देशों को तिब्बत में गलत कामों के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने के बाद ही अपने आर्थिक लाभ को दूसरी प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने करुणा, अहिंसा और सह-अस्तित्व की तिब्बती संस्कृति को रेखांकित किया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसके संरक्षण और समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया।

तिब्बतियों को नस्लीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देने के चीन के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि तिब्बती चीन के नस्लीय अल्पसंख्यक नहीं हैं बल्कि एक विशिष्ट तिब्बती राष्ट्रीयता के लोग हैं। उन्होंने हैम्बर्ग संसद सदस्यों से चीनी कब्जे वाले तिब्बत के अंदर बेजुबान तिब्बतियों की आवाज बनने का आग्रह किया।

अतिथियों ने चल रहे तिब्बती संसद सत्र की कार्यवाही का अवलोकन किया जहां सदन द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

सुश्री अन्ना-एलिजाबेथ वॉन ट्रुएनफेल्स-फ्रोवेन का जन्म १९६२ में फ्रीबर्ग (एल्बे) में हुआ था। वह शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हैम्बर्ग और म्यूनिख में कानून की पढ़ाई की। १९९१ में अपनी पहली सरकारी कानून परीक्षा और १९९५ में दूसरी सरकारी कानून परीक्षा पास की। १९९६ से २००८ तक वॉन ट्रुएनफेल्स-फ्रोवेन ने कई साल ब्राजील में बिताए। जनमत संग्रह के लिए उनका २००८ का समर्थन 'हम सीखना चाहते हैं!' ने उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर मुहर लगा दी और २००९ में वह एफडीपी में शामिल हो गईं। वह २०१७ से हैम्बर्ग राज्य संसद (बर्गर्सचाफ्ट) की सदस्य और २०१८ से एफडीपी के संघीय कार्यकारी बोर्ड की सदस्य बनी हुई हैं।

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tashi Dekyi
Acting Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

ताशी देकि
कार्यवाहक समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578
ई–मेलः coordinator@indiatibet.net

March, 2024, Years: 45 Issue: 03 Regd No. : RNI 34636-79

तिब्बती आवासीय विद्यालय: चीन पर भाषा विनाश की कोशिशका आरोप

जर्मन और ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडलों ने तिब्बतियों के
साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की